'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.02.2015
Date of Posting on concessional rate : 2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 6 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 फरवरी, 2015

दलितों को पुनर्विचार करना चाहिए

डॉ. उदित राज

हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधान सभा के चुनावों से साबित हो गया है कि अब मायावती जी दलितों की मसीहा नहीं रहीं.....

एक समय था जब संसद में (राज्य सभा-सदस्यों को मिलाकर) बसपा के 40 सांसद थे, तो भी मायावती जी ने संसद में दलित हितों का मुद्दा नहीं उठाया.....

हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधान सभा के चुनावों से साबित हो गया है कि अब मायावती जी दलितों की मसीहा नहीं रहीं। 2008 के दिल्ली विधान सभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को 14 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और इस बार यह गिरकर लगभग 1 प्रतिशत रह गया है।

मैंने लगभग एक दशक तक दलित समाज को राजनैतिक स्तर पर संगठित करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात को नहीं समझा गया, उल्टे आरोप लगा कि मैं मायावती जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूं। अधिकांश दलित समाज ने मुझे समाजिक स्तर पर सहयोग किया लेकिन राजनैतिक स्तर पर साथ नहीं दिया। यहां यह बात तो समझ में आती है कि वे राजनैतिक स्तर पर मायावती जी को ही एकमात्र नेता के रूप में स्वीकार करते थे और वे उन्हें कमजोर नहीं करना चाहते थे। प्रश्न उठता कि कि बसपा के समर्थकों ने अब दलितों को आम आदमी पार्टी के साथ जाने से रोकने के लिए ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया ?क्या इसलिए कि आम आदमी पार्टी उनके अधिकार व सम्मान दिलाएगी ?

अगर ऐसा सोचते हैं, तो यहां उसी गलती की पुनरावृत्ति होने जा रही है, जो दलितों व आदिवासियों ने वामपंथी पार्टियों को समर्थन देकर की थी ?वामपंथी पार्टियों के कार्यक्रम व नीतियां आम आदमी पार्टी की ही तरह थी और दलितों का यह भ्रम दूर होने में लगभग दो पीढ़ियां निकल गयीं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों की लगभग 35 वर्षों तक सरकार रही लेकिन वहां पर दलितों की दशा बहुत ही दयनीय बनी हुई है। वहां पर दलितों का नेतृत्व उभरने की बात तो दूर की है, यह राज्य आरक्षण लागू करने में भी अन्य राज्यों से पीछे रहा। इस भयंकर गलती की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है ? जब तक दलितों को आभास होगा, कम से कम एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी होगी।

इस भयंकर गलती के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए बसपा और कुछ दलित कर्मचारी/अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी को समर्थन करने से दलितों को रोकने के लिए आगे आना चहिए लेकिन ये तथाकथित अम्बेडकरवादी ऐसा करने में असफल क्यों हो रहे हैं ?

ये तथाकथित अम्बेडकरवादी ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बढ़ने देने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने बहुत से अधिकार सुनिश्चित करवाकर अपने आपको सबित कर चुका है लेकिन फिर भी तथाकथित मिश्नरी दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। वे कभी आरोप लगाते हैं कि हम उनकी बहनजी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी कहते हैं कि डॉ0 उदित राज कांग्रेस व भाजपा के मोहरे हैं। इन दुष्प्रचारों के कारण हम अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। यह सही है कि जाति के आधार पर लोग तेजी से संगठित हुए लेकिन अब बसपाईयों का भ्रम टूटने लगा है क्योंकि अब जातिवाद की भावना तेजी से टूट रही है। शायद परिसंघ ही देश का एक मात्र संगठन है, जो जातिवाद की बात नहीं करता। किसी भी दलित संगठन को देखा जाए तो पता चलता है कि लगभग सभी संगठनों में नेतृत्व और ज्यादातर समर्थक एक ही जाति से मिलेगें। डॉ0 उदित राज जिस जाति में पैदा हुए, यह उनके वश की बात नहीं थी, उनके लिए मानवता प्रथम है न कि जाति। उनके नेतृत्व वाले अनुसूचित जाति/जन जाति परिसंघ में उनकी जाति के लोग एक प्रतिशत भी नहीं होगें।

क्या इस तरह का कोई अन्य दलित संगठन देश में है, जिसमें किसी विशेष जाति का प्रभुत्व न हो ? ज्यादातर संगठन जात-पांत के आधार पर ही अस्तित्व में हैं। परिसंघ दावा करता है कि डॉ0 उदित राज की जाति के एक प्रतिशत लोग भी संगठन में नहीं हैं। परिसंघ में उसी को पदाधिकारी बनाया जाता है जो योग्यता, प्रतिबद्धता एवं समाजिक न्याय के प्रति समर्पण की भावना रखता है। डॉ0 अम्बेडकर ने जातिहीन समाज की कल्पना की थी लेकिन आज ठीक उसके विपरीत हो रहा है। ये मनुवादियों से किस तरह से भिन्न हैं ? कम से कम अब तो सभी अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को 'अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ' के बैनर तले एकजुट हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दलितों को अधिकार व सम्मान दिलाने हेतु कोई अन्य विकल्प नहीं है।

दलितों व आदिवासियों का असली शत्रु कौन है ? निश्चित रूप से यही तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं। यदि ये वास्तव में मायावती जी के नेतृत्व को बचाए रखना चाहते हैं तो इन्हें अपने कार्यकर्त्ताओं को आम आदमी पार्टी की ओर जाने से रोकना होगा। ऐसा नहीं है कि यह उनके वश की बात नहीं है। जब ये इन कार्यकर्त्ताओं को हमारी ओर आने से रोक सकते हैं तो उन्हें वहां भी जाने से रोका जा सकता है। इसलिए असली शत्रु हमारे में से ही हैं। तथाकथित अम्बेडकरवादी बसपाइयों के जातिवाद का यह चरम नहीं तो क्या है ? मायावती जी का नेतृत्व हमारे अधिकार व सम्मान नहीं सुरक्षित करवा सकता क्योंकि बसपा का तेजी से पतन हो रहा है। यदि बसपा बढ़ती है तो भी दलितों के सम्मान और अधिकार नहीं बच सकते। एक समय था जब संसद में (राज्य सभा सदस्यों को मिलाकर) बसपा के 40 सांसद थे, तो भी मायावती जी ने संसद में दलित हितों का मुद्दा नहीं उठाया। किसी के लिए भी मायावती से मिलना और चर्चा करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अब समय आ गया है पूरे देश के अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग पुनर्विचार करें और डॉ0 उदित राज के नेतृत्व वाले अनुसूचित जाति जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के साथ एकजुट हो जाएं, तभी जाकर अधिकार व सम्मान सुरक्षित रह सकते हैं। +++

वेलेंटाइन डे विरोध के पीछे का अर्थशास्त्र

एच. एल. दुसाध

भारत में पश्चिम की बहुत सी चीजें भारी लोकप्रिय होती जा रही हैं। इनमें 'वेलेंटाइन डे' की बात ही निराली है। शहरी भारतीय युवाओं के बीच यह साल दर साल और लोकप्रिय होते जा रहा है। इससे 14 फरवरी की पहचान वेलेंटाइन डे के रूप उसी तरह स्थापित होती जा रही है। जैसे 14 जनवरी की मकर संक्रांति व 17 सितम्बर की विश्वकर्मा पूजा के रूप स्थापित हो चुकी है। बहरहाल वेलेंटाइन डे के दिन ढेरों हिंदुत्ववादी संगठन वेलेंटाइनी युवक-युवतियों और इनके लिए उपहार बनाने व बेंचने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध यम की भूमिका में अवतरित होकर इस प्रेम-पर्व को विघ्नित करने का सबल प्रयास करते हैं। बहरहाल हिंदुत्ववादियों का वेलेंटाइन विरोध अब एक बड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन की मांग करने लगा है। आखिर जो हिन्दू अपने दैनंदिन जीवन में पश्चिम की सभ्यता-संस्कृति के समक्ष पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिए हैं,वे वेलेंटाइनी युगलों के विरुद्ध क्यों खौफनाक तेवर अपनाते हैं ? काबिले गौर है कि हिन्दुत्ववादी भी अंग्रेजी तिथियों के अनुसार ही अपनेआत्मीय-स्वजनोंयहेडगेवार, गोलवरकर,डीडी उपाध्याय,वाजपेयी इत्यादि का जन्म व मरण दिवस मनाते है।

ये भी आम हिन्दुओं की तरह काका-काकी नहीं,बल्कि अपने बच्चों को अंकल-आंटी, पापा-मम्मी कहना सिखलाते हैं और उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला कराकर गर्व महसूस करते हैं। यही नहीं ये भी अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैण्ड में बसाने के लिए 33 करोड़ देवताओं से मन्नत मांगते रहते हैं। कहने का आशय यह है कि आम हिन्दुओं की भांति ही राष्ट्रवादी हिन्दू भी स्वदेशी संस्कृति को तिलांजलि देकर वेस्टर्न कल्चर के अभ्यस्त हो चुके हैं, फिर क्यों वे वेलेंटाइन युवा-युवतियों और उनके लिए गिफ्ट बेचनेवालों के खिलाफ यम की भूमिका अख्तियार करते हैं ? इसका जवाब वर्ण व्यवस्था के अर्थशास्त्र में निहित है। सभी जानते हैं कि वर्ण-व्यवस्था के प्रवर्तक विदेशी आर्य अर्थात विश्व के प्रचीनतम साम्राज्यवादी रहे। आप यह भी जानते हैं कि सारी दुनिया के साम्राज्यवादियों का ही प्रधान लक्ष्य ही पराधीन बनाये गए मुल्क के शक्ति स्रोतो (आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक इत्यादि) पर कब्जा जमाना तथा वहां के मूलनिवासियों के श्रम का प्रायः निःशुल्क इस्तेमाल अपने वर्ग के हित में करना रहा है।

भारत पर विजय हासिल करने वाले आर्य भी सारी दुनिया के साम्राज्यवादियों की कॉमन सोच के अपवाद नहीं रहे। उन्होंने भी शक्ति के स्रोतों पर चिरकाल के लिए अपना आधिपत्य कायम करने तथा मूलनिवासियों को निःशुल्क दास के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे हम वर्ण-व्यवस्था के रूप में जानते है।

शक्ति के स्रोतों पर चिरस्थाई कब्जे का ऐसा सिस्टम मानव जाति के इतिहास में कोई भी अन्य साम्राज्यवादी कौम विकसित नहीं कर पायी। इस कारण ही आज उनकी मौजदा पीढ़ी का शक्ति सभी स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्जा है। बहरहाल वर्ण-व्यवस्था नामक अपने अर्थ-व्यवस्था को चिरस्थाई एवं हर आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए आर्यो ने एकाधिक उपाय किया।

सबसे पहला उपाय उन्होंने इसे मानव की बजाय ईश्वरकृत प्रचारित करने का उद्योग लिया जिसके तहत भूरि-भूरि शास्त्रों का सृजन किया। इन शास्त्रों द्वारा आर्य मनीषा ने जगत मिथ्या,ब्रह्म सत्य का प्रचार चलाते हुए जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया-'मोक्ष'.मोक्ष के लिए उन्होंने अनिवार्य किया कर्मदृशुद्धता, साथ ही निषेध किया कर्म-संकरता। कर्म शुद्धता का मतलब यह था कि हिन्दू ईश्वर के विभिन्न अंगों से जन्मे चार किस्म के लोग शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहें। विपरीत इसके कर्म-संकरता का पालन करने अर्थात दूसरे वर्ण का निर्दिष्ट पेशा अपनाने पर नरक में जाना अवधारित बताया। कर्म-शुद्धता का अनुपालन और कर्म-संकरता से विरत रखने के लिए उन्होंने 'राज्य की उत्पत्ति' का सिद्धांत विकसित किया। कर्म-शुद्धता के अनुपालन के नाम पर आर्य पुत्रों-ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्यों- का शक्ति के तीनो प्रमुख स्रोतों पर चिरकाल के लिए कब्जा जमाये रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विपरीत उसके आर्य मनीषियों ने मूलनिवासियों को तीन उच्चतर वर्णो की सेवा का निष्काम कर्म करते तथा कर्म-संकरता से विरत रखते हुए शक्ति के स्रोतों से चिरस्थाई तौर पर बेदखल कर दिया। यह तो अंग्रेज भारत में जन्मे फुले, शाहूजी, पेरियार और बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर इत्यादि का अक्लांत संघर्ष था जिसके फलस्वरूप मूलनिवासियों को शक्ति के स्रोतों में कुछ-कुछ हिस्सेदारी मिली। बहरहाल आर्य मनीषी शक्ति के स्रोतों को कब्जाने के लिए कर्म-शुद्धता की अनिवार्यता और कर्म-संकरता के निषेध का ही सिद्धांत रचकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें डर था कि दैविक-गुलाम मूलनिवासी हमेशा के लिए वीभत्स-संतोषबोध के शिकार नहीं रहेंगे। वे भी भारत भूमि की मुक्ति तथा शक्ति के स्रोतों में अपना वाजिब शेयर लेने के लिए संगठित प्रयास कर सकते हैं।

उनके भावी संगठित प्रयास के निर्मूलन के लिए ही वर्ण-व्यवस्था के प्रवर्तकों ने भारत समाज को विच्छिन्नता, द्वेष और परस्पर-शत्रुता की बुनियाद पर विकसित करने की परिकल्पना की। इसके लिए उन्होंने कर्म-शुद्धता की अनिवार्यता तथा कर्म-संकरता के निषेध के साथ ही वर्ण-शुद्धता की अनिवार्यता तथा वर्ण-संकरता के निषेध का सूत्र भी रचा। चूँकि वर्णान्तर विवाह के फलस्वरूप विभिन्न जातियों में भ्रातृत्व विकसित हो सकता था इसलिए सजाति-विवाह के कठोरता पूर्वक अनुपालन करने का उपाय रचा। सजाति विवाह के फलस्वरूप न सिर्फ हिन्दुओं की नस्ल दूषित हुई बल्कि यह समाज चूहे की एक-एक बिल के समान असंख्य भागों में बंटने के लिए अभिशप्त हुआ। विजातीय विवाह की सम्भावना को ही निर्मूल करने के लिए ही आर्यो ने सती-विधवा और बालिका विवाह-प्रथा को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में आर्यो ने हिंदुत्व के अर्थशास्त्र को अटूट रखने के लिए ही सती जैसी अमानवीय प्रथा के तहत भारत के समग्र इतिहास में सवा करोड़ नारियों को भून कर मार डाला तो विधवा प्रथा के तहत कोटि-कोटि नारियों को बर्फ की सिल्ली में तब्दील कर दिया। शक्ति के स्रोतों पर अपना कब्जा अटूट रखने के लिए उन्होंने अरबों बच्चियों को बाल्यावस्था से सीधे युवावस्था में उछाल दिया। शक्ति के स्रोतों पर कब्जा जमाये रखने के लिया आर्यों ने अन्य कई उपायों के साथ सजाति-विवाह की जो व्यवस्था दी उसे तोड़ने में वेलेंटाइन पर्व सक्षम है। क्योंकि इसमें अंतरजातीय-विवाह के बीज हैं। अतः जो आर्य शक्ति के स्रोतों पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिए सदियों से सती-विधवा और बालिका विवाह-प्रथा के तहत आधी आबादी के साथ घोरतर अमानवीय व्यवहार किये, उनकी वर्तमान पीढ़ी वेलेंटाइन डे जैसे प्रेमोत्सव को सहजता से कैसे संपन्न होने देगी जिसमें अंतरजातीय विवाह के बीजारोपड़ का थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा तत्व है! चूंकि वेलेंटाइन के विरोध के पीछे परोक्ष लक्ष्य आर्य पुत्रों का शक्ति के स्रोतों पर अपना प्रभुत्व अटूट रखने के लिए समाज को विच्छिन्न रखना है इसलिए मूलनिवासियों को इस महान पर्व को बढ़ावा देने में सर्वशक्ति लगानी चाहिए। +++

डॉ0 उदित राज ने पश्चिमी यमुना नहर पर पुल बनाने हेतु अपने फंड से दिए लगभग एक करोड़

5 फरवरी 2015.

डॉ. उदित राज के संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में पश्चिमी यमुना नहर पर पुराना बना हुआ पुल वर्षो पहले ढह गया था, जिससे आस-पास नरेला व रोहिणी विधान सभा के गांवों के लोगों के लोगों को आने-जाने हेतु कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था।

इस संबंध में प्रभावित गांव वालों ने डॉ. उदित राज, सांसद, के समक्ष अपनी समस्या रखी और आग्रह किया कि वे अपने एम.पी. लैड से उपरोक्त पुल बनवाएं। डॉ. उदित राज ने पहले तो अपने प्रतिनिधियों को क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया और आज दोपहर 1 बजे वे स्वयं सिंचाई विभाग, हरियाणा व दिल्ली नगर निगम के उच्च

अधिकारियों को मौके पर (पश्चिमी यमुना नहर, सेक्टर, 28, दिल्ली) बुलाकर एक जनसभा की और अधिकारियों को उपरोक्त पुल बनाने से संबंधित दिशानिर्देश दिए। उन्होनें अपने फंड से 80 लाख रूपये उपरोक्त पुल के निर्माण हेतु जारी किया। आवश्यक विभागीय कार्यवाही के पश्चात् शीघ्र ही पुल का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। डॉ0 उदित राज के इस प्रयास हेतु जनसभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने नारे लगाकर डॉ. उदित राज जी का आभार व्यक्त किया।

रोहिणी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर डॉ0 उदित राज जी ने संबंधित अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

उपरोक्त कार्यक्रम में जाने के लिए डॉ. उदित राज जी रवाना ही हुए थे कि ख़बर आई कि रोहिणी में जयपुर गोल्डन हास्पिटल के पास, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पिलर नं. 23 के पास प्रातः 10 बजे के आस-पास दुघर्टना हो गयी है। उपरोक्त फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान एक पिलर का टुकड़ा सड़क पर चलती हुई गाड़ी पर गिर गया, जिससे कि कुछ लोग घायल हो गए।

उन्होंने तुरंत ही घटना स्थल पर संबंधित डी.सी.पी., डी.सी. (राजस्व) व पी.डब्ल्यू.डी. के उच्चाधिकारियों को बुलाया। उन्होनें संबंधित अधिकारियों के साथ घटना स्थल का मुआयना किया और अतिशीघ्र पी.डब्ल्यू.डी. और ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। घटना में घायल हुए लोगों के उपचार हेतु आवश्यक निर्देश दिए। +++

हरियाणा सरकार पदोन्नति में आरक्षण के लिए राजी

हरियाणा में रिजर्व कैटिगरी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का फायदा मिलने जा रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस मामले पर पी. राघवेंद्रा राव कमिटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को नौकरियों के लिए अप्लाई करने के मामले में भी छूट दी है। इसके अलावा राज्य में फैमिली पेंशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब परिवार की बेटी को भी बेटों की तरह आजीवन पेंशन दी जाएगी।

ये फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। राज्य की बीजेपी सरकार ने नई परंपरा शुरू करते हुए कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर सदस्य वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से करवाई। इस मामले में खट्टर सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को फॉलो किया है। कैबिनेट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर कमिटी के तीनों प्रमुख बिंदुओं पर सहमति दे दी। मंत्री ने कहा कि पी. राघवेन्द्र राव कमिटी ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिले आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है।

कमिटी ने सरकार की सार्वजनिक नियुक्ति में सभी कैटिगरियों में सभी श्रेणियों के 3,81,847 कर्मचारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। कमिटी का निष्कर्ष है कि राज्य की कुल जनसंख्या में, अधिकतर प्रमोशन ग्रेड में, लगभग सभी स्तरों पर और राज्य के अधिकतर विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। +++

आरक्षण से कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होती

रेलवे विभाग के कई जोनों में आरक्षण से उत्पादकता में अच्छा प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण के कारण कार्यक्षमता व उत्पादकता पर हुए एक अध्ययन में यह साबित हो गया है कि आरक्षण से कार्यक्षमता व उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ क्षेत्रों में इसके अच्छे परिणाम आएं हैं।

अश्विनी देशपांडे, प्रोफेसर – दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एवं थामस विसकोफ, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) – मिसिगन विश्वविद्यालय ने शोध से संबंधित अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को आरक्षपण देने के कारण भारतीय रेलवे में 1980 एवं 2002 की अवधि का अध्ययन किया, जिसकी रिपोर्ट 'वर्ल्ड डेवलपमेंट जोर्नल' में छपी। भारतीय रेलवे पूरे विश्व में सबसे बड़ा नियोजक (नौकरी देने वाला) है, जहां पर आरक्षण लागू है। रेलवे में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक में मिलाकर लगभग 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं। 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं 7. 5 प्रतिशत जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण लागू है। इस अध्ययन ने पाया कि ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी आरक्षण के कारण ही इन पदों पर पहुंच सकें हैं।

यद्यपि किसी एक व्यक्ति का उत्पादकता पर कितना प्रभाव है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

प्रो0 देशपांडे एवं प्रो0 विसकोफ ने उन जोनों की तुलना की जिनमें ज्यादा दलित कर्मचारी अधिक कार्यरत् थे और जिनमें कम कार्यरत् थे। उन्होंने पाया कि दोनों जोनों में कार्यक्षमता और उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है, उल्टे उन्होंने पाया कि कुछ जोन जिनमें दलित कर्मचारी ज्यादा थे, वहां ज्यादा उत्पादकता हुई है। +++

साजिश के द्वारा दलित राजनीति में आया जातिवाद खत्म करना होगा डॉ0 उदित राज

दलित समाज ने मुझे क्या दिया और मैंने क्या नहीं किया इस पर चर्चा की जरूरत, समय रहते नई दलित राजनीति की शुरूआत करे दलित समाज

मुरादाबाद, 15 फरवरी 2015.

बुद्धिविहार में राजपाल जाटव के आवास पर आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के बैनर तले वर्तमान में दलित समाज के समक्ष चुनौतियां एवं उनके समाधान पर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद उदित राज ने कहा कि मैंने अपने लोगों से वोट मांगा तो जमानत जब्त करा डाली, जो केवल दलित राजनीति में जातिवाद की देन थी जिसे खत्म करना होगा। जबकि मैं हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ाता रहा हूं।

आपका वोट पाने वाली मायावती ने न तो आपको आन्दोलनकारी बनने दिया और न वे आपकी लड़ाई लड़ सकी, यदि वे चाहती तो राज्यसभा व लोकसभा में 45 सासंदों के द्वारा आपके हितों की बातें रख सकती थीं, लेकिन मैंने सांसद बनने के बाद संसद में कई बार आपकी आवाज बुलंद की, एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि नई दलित राजनीति की शुरूआत करो यदि आप लोग मजबूती से मेरे साथ खड़े होते हैं तो मैं अपनी पार्टी से दलित समाज के लिये काफी कुछ कराता रहूंगा, हालांकि उदित राज कल हर मौके पर अपनेपन के साथ अपना दुख प्रकट करना नहीं भूले और कहने लगे कि आप लोगों का सपा, भाजपा, कांग्रेस अधिकार मांगना बेईमानी है, जिसको वोट देते रहे तो उससे सवाल जवाब क्यों नही करते। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद मुरादाबाद मन्डल के पांचों जिलों से आये पदाधिकारियों से कहा कि दलित समाज के लोग मेरी जाति देखते हैं, अरविंद केजरीवाल की जाति नहीं देखते। कम से कम अपनी कमान दूसरों के हाथ में तो मत सौंपो मेरे कहने से ही वोट दे दिया होता तो आज मैं सरकार से आपके अधिकार झगड़कर भी ले लेता, लेकिन वोट के समय मायावती व दूसरों को छोड़ना पड़ेगा, भला जो नेता बिना पढ़े नहीं बोल सकती, वह भ्रष्टाचारी होकर कैसे आपकी लड़ाई लड़ सकती है। मैं सत्ता में रहकर भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं उन्होंने एक सोची समझी योजना के तहत लाभ के पद पाने को फर्जी जाति प्रमाण पत्र अथवा दलित महिलाओं से शादी करने वालों की सूची देने का अनुरोध किया और कहा कि मीडिया ऐसे लोगों के नाम क्यों प्रकाशित नहीं करता। श्री राज ने कहा कि अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध मायावती ने दलितों को संघर्ष करना नहीं सिखाया, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सीखो, मुझे याद करोगे तो मैं वहीं मिलूंगा। मैं बसपा की तरह नहीं हूं कि अपनी बात रखने वालों को संगठन से बाहर कर दूं, मुझे तो अपने नारे लगवाने व अखबारों में न्यूज प्रकाशित कराने वाले अपने नेता अच्छे लगते हैं। उन्होंने अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध महाराष्ट्र के पेपर आन्दोलन से सीख लेने की अपील की तथा कहा कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को सही मार्ग दर्शन कराना चाहता हूं। यूपी में परिसंघ भंग चल रहा है, नई ऊर्जा के साथ कमेटी बनानी है यदि समय रहते समाज समझ गया तो ठीक है वरना आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। आप लोगों ने मेरे साथ कितना भी अन्याय किया हो लेकिन मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा। मेरे पास अपने लिए सब कुछ है, समाज के ठेकेदारों के चुंगल से निकल संघर्षशील बनाना चाहता हूं कि, यही मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि मीडिया आपसे दूरी बनाकर रखता है सही कवरेज नहीं देता, तो आप लोग भी उससे दूरी बनाकर अपने न्यूज चैनल व पेपर चलाकर सोशल मीडिया का रास्ता पकड़ लो। कई सफलता पाने वाले सोशल मीडिया की देन है। सभी लोग व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर व इन्टरनेट का इस्तेमाल करें, एक मिनट में करोड़ो लोगों तक पहुंचाना केवल सोशल मीडिया को ही वरदान है। गोष्ठी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी केदारनाथ सिंह, राजपाल सिंह जाटव, बिजनौर जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश सिंह, सुरेन्द्र नवल, मोहर सिंह मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, अमरोहा जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह, सम्भल जिलाध्यक्ष सेवाराम दिवाकर, राजेन्द्र सिंह, बदायुं ईश्वर चन्द्र मुरादाबाद, लखपत सिंह मुरादबाद, केपी सिंह बिजनौर, अम्बेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह मौर्य एडवोकेट, वरिष्ठ दलित वरिष्ठ दलित नेता मदन भारती सहित सैकड़ों महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। साभार – विधान केसरी +++

आदिवासी छात्रों के स्कॉलरशिप में हजार करोड़ का गबन

यह घोटाला हजारों करोड़ का है और इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल हो सकते हैं। दरअसल अनुसूचित–जाति, जनजाति के इन बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार वजीफा देती है, जिसकी आड़ में महाराष्ट्र के कई जिलों में हजारों करोड़ के फर्जीवाड़े का खेल शुरू हुआ।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में गढ़चिरौली की लोकल क्राइम ब्रांच ने अभी तक नौ शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच लोगों को गिफ्तार किया है।

एक अनुमान के मुताबिक, यह घोटाला हजारों करोड़ का है और इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल हो सकते हैं। दरअसल अनुसूचित–जाति, जनजाति के इन बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार वजीफा देती है, जिसकी आड़ में महाराष्ट्र के कई जिलों में हजारों करोड़ के फर्जीवाड़े का खेल शुरु हुआ।

बच्चों के नाम पर फर्जी एडमिशन लिए गए। आरोप है कि वजीफे की रकम इन संस्था के संचालकों ने हड़प ली। मामले की जांच में जुटे गढ़चिरौली लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रविंद्र पाटिल ने बताया कि गढ़चिरौली में जो संस्थापक हैं, उन्होंने फर्जी फार्म इकट्ठा किए, एजेंट बनाए और घर पर जाकर खेती में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले ऐसे बच्चों के फार्म इकठ्ठा किए, उनका ऑनलाइन फार्म खुद उन्होंने भरा, साइन किए और फार्म जमा किए, 300 बच्चों का फार्म भर कर उनका पैसा कालेज के एकाउंट से ले लिया। यही नहीं तय संख्या से ज्यादा 300 और बच्चे जो अनुसूचित जाति, डीटीएनटी और ओबीसी वर्गों से आते थे, उनके लिए भी समाज कल्याण विभाग से स्कालरशिप ली।

पाटिल के मुताबिक, यह घोटाले पिछले कई वर्षो से जारी है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग फर्जी संस्थाएं खड़ी कर पिछले चार साल से करोड़ों की स्कालरशिप हड़प चुके हैं। हमने जब जानना चाहा तो पता लगा कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से तकनीकी शिक्षा लेने वाले हर एससी–एसटी छात्र पर महाराष्ट्र सरकार 48000 रुपये सालाना खर्चती है, जिसमें 2300 रुपये छात्र के खाते में जमा होते थे, 9000 रुपये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ज्ञानमंडल के खाते में, जबकि बाकी के तकरीबन 35,000 रुपये संस्था के खाते में। लेकिन जब कुछ चेक वापस आने लगे, तो प्रशासन को शक हुआ और मामले की जांच शुरु हुई तो हजारों करोड़ के इस घोटाले की परतें खुलने लगीं। पुलिस को लगता है कि मामले में कई सरकारी अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है।

पाटिल कहते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि फर्जी कागजातों के बिना पर करोड़ों रुपये नहीं निकाले जा सकते। इन संचालकों ने वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया और भी कई जिलों में ऐसे ही कालेज वहां बनाए हैं, हमने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच शुरु है।

इस योजना के तहत वर्धा की एक संस्था ने पुणे की एक संस्था के साथ मिलकर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ज्ञानमंडल की स्थापना की थी। साल 2010 में ज्ञानमंडल ने पूरे राज्य में 262 स्टडी सेंटर को मान्यता दी, जो 2–3 कमरों में चलते थे, ज्यादातर सेंटरों में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक एक ही शख्स था। पुलिस ने अभी तक 9 संस्थाओं के फर्जीवाड़े को उजागर करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे शक है कि सभी 262 संस्थाएं फर्जी हो सकती हैं और इन्हें चलाने में सरकारी तंत्र में बैठे बड़े सफेदपोश शामिल हो सकते हैं। +++

ओबामा बोले, भारत में धार्मिक असहिष्णुता से आहत होते गांधीजी

वाशिंगटन, 6 फरवरी 2015.

भारत में सभी समुदायों ने पिछले कुछ वर्षो में जिस धार्मिक असहिष्णुता का अनुभव किया है उससे महात्मा गांधी आहत हुए होते। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। ह्वाइट हाउस ने एक दिन पहले ही ओबामा के नई दिल्ली में दिए सार्वजनिक भाषण के दौरान धार्मिक असहिष्णुता को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर निकाले जा रहे अर्थ को गलत ठहराया था। ओबामा ने नई दिल्ली में धार्मिक सहिष्णुता कम होती जा रही है कहते हुए भाजपा पर निशाना साधा था।

ओबामा ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान कहा, मिशेल और हम भारत से लौटे हैं। एक आश्चर्यजनक, विविधता से भरा सुंदर देश है लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पिछले कुछ वर्षो में सभी तरह की धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्म के लोगों ने समय–समय पर केवल अपनी विरासत और मान्यता की वजह निशाना बनाया है। इस असहिष्णुता की वजह से उस देश को आजाद कराने में मदद करने वाले गांधीजी आहत होते।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले कुछ वर्षो के दौरान भारत में विभिन्न धर्मो को मानने वालों के खिलाफ हुई हिंसा का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने किसी खास धर्म का उल्लेख नहीं किया और कहा कि हिंसा किसी खास समूह या धर्म के लिए खास नहीं है। मानवता इन

सवालों के साथ पूरे मानव इतिहास से जूझ रही है। वह इस कार्यक्रम में जुटे अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तीन हजार से अधिक लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति है यह ऐसी पापमय आदत है कि हमें अपने धर्म से विमुख कर सकती है। इस कार्यक्रम में ओबामा ने तिब्बत के निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामा को एक अच्छा दोस्त बताया।

सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार साथ ओबामा–दलाई लामा

किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा साथ–साथ नजर आए। गुरुवार को मौका था सालाना नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर का। करीब तीन हजार अमेरिकी और वैश्विक नेता इसके गवाह बने।

इस दौरान ओबामा ने दलाई लामा को स्वतंत्रता व गरिमा का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा, व्हाइट हाउस में कई मौकों पर दलाई लामा का स्वागत कर मैंने प्रसन्नता का अनुभव किया है और आज वे यहां हमारे साथ हैं इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

ओबामा का यह बयान चीन को नाराज कर सकता है। उसने इस कार्यक्रम से पहले ही ओबामा को दलाई लामा से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब दोनों की मुलाकात हुई है। इससे पहले तीन बार व्हाइट हाउस में दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस बार ऐसी बैठक की योजना नहीं है।

साभार – दैनिक जागरण +++

विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी

नाम व मोबाइन नंम्बर	प्रदेश
नाहर सिंह - 9312255381	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु
रविन्दर सिंह -7503051128	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
धनंजय सिंह -	दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र
योगेश आनंद - 9654144068 आर0 एस हंस - 9811800137	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
बलबीर सिंह - 9999051041	गुजरात, राजस्थान, जम्मू काश्मीर
भानू पुनिया - 9013332151	पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

हरियाणा एवं गुजरात परिसंघ ने दिल्ली आकर डॉ0 उदित राज से की चर्चा

डॉ0 उदित राज जी के साथ
गुजरात परिसंघ के पदाधिकारी गण

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की गत् 8 दिसंबर की रैली के बाद लगभग सभी प्रदेशों की इकाइयों में शिथिलता आ गयी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज पूरे देश की विभिन्न इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी इकाई को अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से भंग कर दिया गया है। शीघ्र ही उसका भी पुनर्गठन होना है। सबसे पहले गुजरात एवं हरियाणा की इकाइयां अपने प्रमुख पदाधिकारियों के साथ 14 फरवरी, 2015 को दिल्ली आयीं और डॉ0 उदित राज जी से चर्चा किया। गुजरात इकाई की ओर से एन.जे. परमार, रामूभाई बाघेला, पिनाकिन लेउवा, ललिता पिनाकिन, कांतिभाई आर. डाबी, योगराज बाघेला, कोष्ठी विरल, अजय पी. डाबी, चन्द्रकांत सोलंकी, क्रांतिभाई एस. मकवाना, जयेश कुमार चावड़ा, आदि ने दिल्ली पहुंचकर चर्चा में भाग लिया। पदाधिकारियों ने अपने प्रदेश में किस प्रकार से कार्यकारिणी को मजबूत बनाएगें इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज को अवगत कराया। डॉ0 उदित राज जी ने गुजरात एवं हरियाणा दोनो इकाइयों को निर्देशित किया है कि यहां से जाने के बाद वे अपने-अपने प्रदेशों में प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाएं एवं मार्च, 2015 की कोई तिथि तय करके मुझसे समय लेकर अपने-अपने यहां प्रान्तीय सम्मेलन बुलाएं, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी किया जाए। प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जोन, जिले एवं ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी अतिशीघ्र गठित की जाए। डॉ0 उदित राज जी ने सभी प्रदेशों में परिसंघ की स्पेशल मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने के निर्देश दिए। हरियाणा प्रदेश से महासिंह भूरानिया, एस.पी. जरावता, सत्यवान भाटिया, दया राम, रामफल, रामपाल, प्रो. नरेश सिंह, अनूप सिंह, प्रो0 बलदेव सिंह, सुभाष, गिल, ओ.पी. रंगा, ओम नारायण, राम अवतार, वजीर सिंह मेहरा, हरीश कुमार, कंवर सिंह नेताजी, राजपाल, कर्मवीर खींचीं, के.सी. दहिया, राजेश शास्त्री, सतबीर सिंह, बिजली सिंह, शशिकांत धर्मेंद्र सिंह, राजेन्द्र प्रसाद आदि लोगों ने भाग लिया डॉ0 उदित राज जी ने दोनों प्रदेशों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीकी सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। उन्होंने सभी साथियों से आग्रह किया कि वे उनके व्हाट्सअप नं. 09999504477 से जुड़े।

इस पर वे अपनी समस्याओं से लेकर सभी प्रकार की गतिविधियां साझा कर सकते हैं। जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं वे मोबाइल नं. 09015552266 पर एसएमएस कर सकते हैं और राष्ट्रीय कार्यालय से भेजे जाने वाले एस.एम.एस. अगर नहीं मिल रहे हैं तो वे इस नंबर पर मिस काल भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने फेसबुक, ट्वीटर आदि पर जुड़ने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ एवं अन्य जानकारियों के लिए वेबसाइट देखें। इस पर वॉयस ऑफ बुद्धा भी अपलोड किया जाता रहता है। दोनों इकाइयों ने डॉ0 उदित राज जी को आश्वस्त किया है कि वे शीघ्र ही अपने प्रदेशों में परिसंघ की मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगें और विभिन्न पर कार्यकारिणी शीघ्र ही गठन करके राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करेंगी। +++

डॉ0 उदित राज जी के साथ
हरियाणा प्रदेश परिसंघ के पदाधिकारी गण

दुनिया का निराला कवि : नामदेव ढसाल

एच. एल. दुसाध

गत वर्ष 15 जनवरी को दिवंगत होने वाले विश्वकवि नामदेव ढसाल का जन्म 15 फरवरी, 1949 को महाराष्ट्र के पुणे के निकट हुआ था। दलित आन्दोलनों के इतिहास में डॉ. आंबेडकर और कांशीराम के बीच की कड़ी ढसाल की पहचान वैसे तो मुख्य रूप से कवि के रूप में रही है पर, वह एक बड़े चिन्तक,पेंटर,असाधारण संगठनकर्ता और दूरदर्शी राजनेता सहित अन्य कई गुणो के स्वामी थे। अब जहां तक कविता का सवाल है वे नोबेल विजेता कवि टैगोर से भी बड़े कवि थे।

इस मामले में मुझे 2012 में दिल्ली के 20 वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में चर्चित कवि विष्णु खरे की उस टिपण्णी की बार-बार याद आती है जो उन्होंने उनकी हिंदी में पहली अनुदित पुस्तक आक्रोश का कोरस का विमोचन करते हुए कही थी। संयोग से उस विमोचन समारोह में मैं भी उपस्थित था। वैसे तो मैंने एक बड़े कवि के रूप में उनके विषय बहुत कुछ सुन रखा था। किन्तु खरे साहब ने जो सत्योद्घाटन किया, वह चौकाने वाला था। उन्होंने कहा कहा था, पिछले दिनों कोलकाता पुस्तक मेले में आयोजित लेखकों की एक संगोष्ठी में तमाम लोगों ने ही एक स्वर में नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकृति प्रदान किया। किन्तु मेरा मानना है कि ऐसी मान्यताएं ध्वस्त होनी चाहिए। आज की तारीख में रवीन्द्रनाथ ठाकुर पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं।

आज भारत जिन समस्यायों से जूझ रहा है, उसका कोई भी समाधान उनकी कविताओं में नहीं है। अगर कविता का लक्ष्य मानव-जाति की समस्यायों का समाधान ढूँढना है तो मेरा दावा है कि ढसाल, टैगोर से ज्यादा प्रासंगिक और बड़े कवि हैं। उन्होंने आगे कहा था रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग हमारे लिए बोझ हैं जिसे उतारने का काम ढसाल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय कविता जगत में भारतीय कविता का विजिटिंग कार्ड का नाम नामदेव ढसाल है। उन्होंने कविता की संस्कृति को बदला है। यह कविता को परंपरा से मुक्त किया एवं उसके आभिजात्यपन को तोड़ा है।

संभ्रांत कविता मर चुकी है और इसे मारने का काम ढसाल ने किया है। आज हिंदी के अधिकांश सवर्ण कवि दलित कविता कर रहे हैं तो इसका श्रेय नामदेव ढसाल को जाता है। ढसाल ने महाराष्ट्र के साथ देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है, ऐसा काम करनेवाला भारत में दूसरा कोई कवि पैदा नहीं हुआ। नामदेव ढसाल किसी व्यक्ति नहीं, आंदोलन का नाम है। अगर देश में 5,6 ढसाल पैदा हो जाएँ तो इसका चेहरा ही बदल जाय। क्या कोई कवि , वह भी दलित समाज से निकला , नोबेल विजेता टैगोर से बड़ा और ज्यादा प्रासंगिक हो सकता है? बहरहाल नोबेल विजेता की खूबियों से लैस ढसाल एक विशेष नजरिये अपने किस्म के इकलौता कवि रहे। दुनिया में एक से एक बड़े लेखक,समाज सुधारक, राजा महाराजा, व कलाकार पैदा हुए किन्तु जिन प्रतिकूल परिस्थितियों को जय कर ढसाल साहब ने खुद को एक विश्व स्तरीय कवि, एक्टिविस्ट के रूप में स्थापित किया, वह बेनजीर है।

मानव जाति के समग्र इतिहास में किसी भी विश्वस्तरीय कवि ने दलित पैंथर जैसा मिलिटेंट आर्गनाइजेशन नहीं बनाया। दुनिया के दूसरे बड़े लेखक-कवियों ने सामान्यतया सामाजिक परिवर्तन के लिए पहले से स्थापित राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़कर बौद्धिक अवदान दिया। किन्तु किसी ने भी उनकी तरह उग्र संगठन बनाने की जोखिम नहीं लिया। दलित पैंथर के पीछे कवि ढसाल की भूमिका का दूसरे विश्व कवियों से तुलना करने पर मेरी बात से कोई असहमत होना कठिन है।

इसके लिए आपका ध्यान दलित पैंथर की खूबियों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अब से चार दशक 9 जुलाई 1972 को नामदेव ढसाल ने अपने साथी लेखकों के साथ मिलकर दलित पैंथ जैसे विप्लवी संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने डॉ. आंबेडकर के बाद मान-अपमान से बोध शून्य दलित समुदाय को नए सिरे से जगाया था। इससे जुड़े प्रगतिशील विचारधारा के दलित युवकों ने तथाकथित आंबेडकरवादी नेताओं की स्वार्थपरक नीतियों तथा दोहरे चरित्र से निराश हो चुके दलितों में नया जोश भर दिया जिसके फलस्वरूप

(शेष पृष्ठ 6 पर)

Quotas do not hurt efficiency, says study

Rukmini S.

5 Feb. 2015

A first-of-its-kind study of the impact of reservations in public sector jobs on productivity and efficiency has shown that the affirmative action did not reduce productivity in any sector, but had, in fact, raised it in some areas.

Despite being widespread and much-debated, India's reservation policy for the educationally and socially backward classes is poorly studied. While there is some research into the impact of reservations in politics and in higher education, there has been no study yet of its impact on the economy.

In the pioneering study, Ashwini Deshpande, Professor at the Delhi School of Economics, and Thomas Weisskopf, Professor of Economics at the University of Michigan, measured the impact of reservation for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) on productivity and efficiency in the Indian Railways between 1980 and 2002. The study was published in the World Development journal.

The Indian Railways is the world's largest employer where affirmative action applies, Ms. Deshpande said. It employs between 1.3 and 1.4 million people at four levels of employment — Group A to Group D, with Group A employees being the senior-most. There is 15 per cent reservation for the SCs and 7.5 per cent reservation for the STs at all levels, with additional reservation for Other Backward Classes (OBCs). The study looked at SC and ST employees in Group A and B only, since people from marginalised backgrounds would have been unlikely to reach high levels of employment without reservation.

Since an individual's impact on productivity is impossible to estimate, Ms. Deshpande and Mr. Weisskopf compared zones and periods of time with higher numbers of SC and ST employees with those with lower numbers, keeping other variables constant. They found no negative impact on productivity and efficiency in any area, and some positive effects in some areas of work.

"Beyond the numbers, we can speculate about the reasons for why there might be some positive impact of affirmative action," Ms. Deshpande explll ained. "Individuals from marginalised groups may be especially highly motivated to perform well when they attain decision-making and managerial positions, because of the fact that they have reached these positions in the face of claims that they are not sufficiently capable, and they may consequently have a strong desire to prove their detractors wrong," the authors suggested.

This is a possible explanation which rings true for Scheduled Caste employees of the Railways whom The Hindu spoke to. "At every level where there is discretionary power, SC/ ST employees are systematically discriminated against," said B.L. Bairwa, the president of the All-India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees Association.

He cited a number of cases from across the country that he was battling, of deserving backward caste railway employees who had been passed up for promotions, transferred arbitrarily or given adverse records. "When an SC or ST employee rises, he has to prove himself and work extra hard. I am not surprised the efficiency goes up," he said.

(Courtesy - The Hindu) ✦✦✦

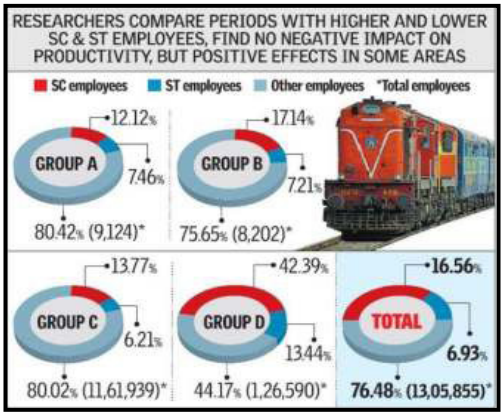

Affirmative action spurs motivation, say researchers

Despite being widespread and much-debated, India's reservation policy for the educationally and socially backward classes is poorly studied. While there is some research into the impact of reservations in politics and in higher education, there has been no study yet of its impact on the economy.

In the first ever study on the issue, evidence on this question, based on research on the Indian Railways, Ashwini Deshpande from the Delhi School of Economics, and Thomas Weisskopf from the University of Michigan, measured the impact of reservation for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) on the Indian Railways between 1980 and 2002.

"Beyond the numbers, we can speculate about the reasons why there might be some positive impact of affirmative action," Ms. Deshpande explained. "Individuals from marginalised groups may be especially highly motivated to perform well when they attain decision-making and managerial positions, because of the fact that they have reached these positions in the face of claims that they are not sufficiently capable, and they may consequently have a strong desire to prove their detractors wrong," the authors suggested.

This is a possible explanation which rings true for Scheduled Caste employees of the Railways whom The Hindu spoke to. "At every level where there is discretionary power, SC/ ST employees are systematically discriminated against," said B.L. Bairwa, the president of the All-India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees Association.

He cited a number of cases from across the country that he was battling, of deserving backward caste railway employees who had been passed up for promotions, transferred arbitrarily or given adverse records. "When an SC or ST employee rises, he has to prove himself and work extra hard. I am not surprised the efficiency goes up," he said. ✦✦✦

Religious intolerance.....

(Cont...from page - 8)

country, slavery and Jim Crow (racial segregation state and local laws) all too often was justified in the name of Christ," he said, addressing a gathering of over 3,000 US and international leaders. "There is a tendency in us, a sinful tendency that can pervert and distort our faith.

In today's world, when hate groups have their own Twitter accounts and bigotry can fester in hidden places in cyberspace, it can be even harder to counteract such intolerance. But God compels us to try. And in this mission, I believe there are a few principles that can guide us, particularly those of us who profess to believe," he said. On Wednesday, the White House had refuted allegations that Obama's remarks in India were aimed at the BJP, saying that the speech in its entirety was about the "core democratic values and principles" of boththe US and India. (Courtesy - The India Express) ✦✦✦

दुनिया का.....

(पृष्ठ 5 का शेष)

उनको अपनी ताकत का अहसास हुआ तथा उनमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की मानसिकता पैदा हुई। इसकी स्थापना के एक महीने बाद ही ढसाल ने यह घोषणा की कि यदि विधान परिषद् या संसद सामान्य लोगों की समस्यायों को हल नहीं करेगी तो पैंथर उन्हें जलाकर राख कर देंगे, शासक दलों में हडकंप मचा दिया। दलित पैंथर के निर्माण के पृष्ठ में अमेरिका के उस ब्लैक पैंथर आन्दोलन से मिली प्रेरणा थी जो अश्वेतों को उनके मानवीय, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकार दिलाने के लिए 1966 से ही संघर्षरत था।

उस आन्दोलन का नामदेव ढसाल और उनके क्रन्तिकारी युवकों पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने ब्लैक पैंथर की तर्ज पर दलित मुक्ति के प्रति संकल्पित अपने संगठन का नाम दलित पैंथर रख दिया। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है पैन्थरों ने डॉ. आंबेडकर की विचारधारा को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे विकसित किया तथा उसी को अपने घोषणापत्र में प्रकाशित भी किया जिसके अनुसार संगठन का निर्माण हुआ। यद्यपि यह संगठन अपने उत्कर्ष पर नहीं पहुच पाया तथापि इसकी उपलब्धियां गर्व करने लायक रही। बकौल चर्चित मराठी दलित चिन्तक आनंद तेलतुम्बडे, इसने देश में स्थापित व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और संक्षेप में बताया कि सताए हुए आदमी का आक्रोश क्या हो सकता है।

इसने दलित राजनीति को एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की जोकि पहले बुरी तरह छूटी थी। अपने घोषणापत्र अमल करते हुए पैन्थरों ने दलित राजनैतिक मुकाम की खातिर परिवर्तनकामी अर्थों में नई जमीन तोड़ी। उन्होंने दलितों को सर्वहारा परिवर्तनकामी वेग की पहचान प्रदान की तथा उनके संघर्ष को दुनिया के अन्य दमित लोगों के संघर्ष से जोड़ दिया। बहरहाल कोई चाहे तो दलित पैंथर की इन उपलब्धियों को खारिज कर सकता है किन्तु दलित साहित्य के विस्तार में इसकी उपलब्धियों को नजरंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दलित पैंथर और दलित साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलूँ हैं।

इसकी स्थापना करने वाले नेता पहले से ही साहित्य से जुड़े हुए थे। दलित पैंथर की स्थापना के बाद उनका साहित्य शिखर पर पहुँच गया और देखते ही देखते मराठी साहित्य के बराबर स्तर प्राप्त कर लिया। परवर्तीकाल में डॉ. आंबेडकर की विचारधारा पर आधारित पैन्थरों का मराठी दलित साहित्य हिंदी पट्टी सहित अन्य इलाकों को भी अपने आगोश में ले लिया। दलित साहित्य को इस बुलंदी पर पहुचाने का सर्वाधिक श्रेय ढसाल साहब को जाता है। गोल पीठा पी बी रोड़ और कमाठीपुरा के नरक में रहकर ढसाल साहब ने जीवन के जिस श्याम पक्ष को लावा की तरह तपती कविता में उकेरा है उसकी विशेषताओं का वर्णन करने की कूवत मुझमे तो नहीं है। ✦✦✦

TS govt. extends hand to Dalit entrepreneurs

5 Feb. 2015.

The Telangana government will provide one acre of land in Hyderabad and Rs.5 crore financial assistance for setting up of a Dalit entrepreneur incubation centre. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao announced this in response to a demand from the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) here on Friday.

Mr. Rao, addressing the three-day industrial and trade expo of DICCI that opened at Hitex here, added that Dalit entrepreneurs desirous of taking up new ventures would also qualify for the benefits being extended by the State government to Dalit entrepreneurs of Telangana.

"All doors are open... Dalit entrepreneurs can come and invest. We will extend the same benefits to them too," said the Chief Minister, who spoke extensively in Hindi.

Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao with Minister of State for Commerce and Industry Nirmala Sitharaman and chairman of the Godrej Group Adi Burjorji Godrej at the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry's Trade Expo that was opened in HITEX at Hyderabad on Friday.

Earlier, founder chairman of DICCI, Milind Kamble, hailed Telangana's industrial policy as 'the best'. "It is also the most Dalit friendly industrial policy," he said.

Expressing happiness at DICCI's emphasis that its members want connections and not concessions and on giving jobs instead of seeking jobs, the Chief Minister said the State government had decided to set aside Rs.5 crore for a scheme under which margin money assistance will be extended to Dalit entrepreneurs. This decision was taken in view of difficulties faced by such entrepreneurs while accessing bank credit.

Promising government support, Mr. Rao said it was also decided to train 200 SC/ST contractors. The State government will allocate a portion of its works to them, he added.

Highlighting the features of the new industrial policy, he said 22 per cent of land in industrial estates would be earmarked for SC/ST entrepreneurs.

Union Minister for Commerce and Industry Nirmala Sitharaman said that with effect from April 1, the public procurement policy, under which a portion of the requirements of government agencies have to be sourced from enterprises run by SC/ST, will come into force. According to the stipulation, four per cent of the 20 per cent procurement reserved for SME units has to be from SC/ST units.

Industrialist and past chairman of CII, Adi Godrej, said that the industry had always been supportive of inclusive growth. Voluntary commitment rather than one mandated is important to create a society of equal opportunities.

(Courtesy - THE HINDU)

+++

Dalit honcho scripts historic buy

Entrepreneur Kalpana Saroj Lobbied Govt To Buy Ambedkar's UK Home

8 Feb. 2015.

MUMBAI: Maharashtra government's successful bid to buy a London house where Dr Babasaheb Ambedkar once lived may never have taken place had Mumbai-based millionaire Kalpana Saroj not spotted the 'For Sale' sign at its door.

The house on King Henry Road where Ambedkar lived while studying at the London School of Economics is a shrine of sorts for Saroj. The chairman of India's constituent assembly and a messiah for Dalits in India, Ambedkar was once a victim of caste-based discrimination while growing up in rural Madhya Pradesh. His story resonates with Saroj, chairperson of Kamani Tubes and winner of the 2013 Padma Shri award.

Two years after Ambedkar's death in 1956, Saroj was born to a poor Dalit family in rural Vidarbha. Married off at the age of 12 to a man many years her senior, she was tormented by her in-laws and her marriage broke down before she turned 13. After a failed suicide bid, she was determined to make something of her life and chose to script her success in Mumbai. When she first arrived in the city, she worked as a seamstress for Rs 2 a day. She then took a loan, turned entrepreneur and finally worked her way up the ladder. Nearly a decade ago, she took control of Kamani Tubes when the company was sick and turned its fortunes around.

Last July, Saroj was in Paris to attend a conference organized by the Ambedkar International Mission, a global organization of Dalits around the world. "After the conference, a few of us headed to London. Whenever we're in the city, we make it a point to visit the house where Ambedkar once lived," says Saroj, who was accompanied on her visit by R K Gaikwad, Maharashtra's former commissioner for social welfare, and Gautam Chakravarthy of the Federation of Ambedkarites & Buddhist Organizations, UK, among others.

We were shocked to find the house was up for sale," she says, adding that it cost Rs 40 crore, more than any Dalit organization could afford.

For the next six months, Saroj teamed up with prominent members of the Dalit community in India and the UK and lobbied with both the Central government and the Maharashtra state government to bid for the house.

While Saroj met National Security Advisor Ajit Doval in Delhi, she lobbied with both the earlier Congress government and the present BJP government in Maharashtra. "I kept getting calls from Santosh Das of the Federation of Ambedkarites & Buddhist Organizations in London, telling me that the house could be sold any minute. Meanwhile, the Maharashtra government was trying to decide whether the bid for the house should be made by the social justice department or general administration. We tried to stress the importance of immediately writing to the owners in London, expressing intent to buy the place. Time was of essence and we were worried that a delay could result in losing the bid," says Saroj.

Needless to say, she is thrilled that the Maharashtra government is set to buy the place and applauds the government on its alacrity. "The house is like a temple of knowledge. After all, this is the place where Babasaheb Ambedkar lived while completing a six-year course in two years flat."

+++

(Courtesy - TIMES OF INDIA)

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 6 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 February, 2015

Dalits should rethink

Dr. Udit Raj

Recent Delhi election has reaffirmed that no longer Ms Mayawati is Dalit icon. In 2008, BSP scored about 14% votes in Delhi election and now it has come down to around one percent. I tried for about a decade to mobilize the Dalits politically but it was not understood, and the reason behind was that it will weaken Mayawati. Most of them supported me socially but remained unfazed giving political allegiance. It was somewhat understandable that they wanted to help in intacting the leadership but the question is that why have the supporters not acted to stop Aam Admi Party as they did to us. Do they think that the leadership of Aam Admi Party will secure rights and dignity? It reminds the same blunder on the part of Dalits and Adivasis when they supported the left parties. The programmes and policies of the left parties were as attractive as Aam Admi Party, and they got disillusioned after nearly two generations. In Bengal, left parties ruled for thirty-five years and the plight of Dalits over there is worse. What to talk about emergence of political leadership, the reservation achieved there less than that of any State. Why this blunder is being committed again, and by the time Dalits will realize, a generation must have been wasted. Who are responsible for this great blunder? None other than supporters of BSP and SC/ST employees. They could have come out to stop the support to Aam Admi Party but why these so called Ambedkarites failed to do so?

These so called Ambedkarites are responsible for the growth of Aam Admi Party in Delhi. This is based on truth experienced by All India Confederation of SC/ST Organizations despite the fact that we delivered best results and yet these so-called missionaries kept on rumouring on number of counts. Sometimes they made allegations that we were weakening their Behanji and on other times throwing mud that Udit Raj is either a stooge of Congress or BJP. This propaganda affected us a lot and our struggle could not yield the desired results. It is true that strong mobilization is done in line of caste but that has got its duration. The followers of BSP are getting disillusioned because caste emotion is lasting fast.

Perhaps the Confederation is the only organization in the country which knows no caste. If the rank and file of any Dalit organization is evaluated, most of them will have leaders and workers from same caste of that of leadership. What caste Dr. Udit Raj had to be born, it was not within his command but for him only human beings exist and not the caste and to know it one has to look at rank and file of Confederation, not even one percent are from his sub caste. Is there any Dalit Adivasi organization in the country which is not dominated by the rank and file of the caste of leadership? Most of them are surviving on the support of their sub caste people. The Confederation throws challenge to reveal the rank and file of workers and leaders, one will not find even one percent workers of the caste which Dr. Udit Raj belonged to. Sheer on the basis of qualities, commitment and belief in ideology of social justice, the position has been given in the Confederation. Dr. Ambedkar preached to work for casteless society but what it happening. Are they better than Brahminical forces? So much has gone by. At least now all Dalits and Tribals should come together under the umbrella of All India Confederation of SC/ST Organizations. There is no other alternative left to save the dignity and rights of the Dalits.

Who is the real enemy of Dalits and Adivasis? - Certainly these so called Ambedkarites. If they really wanted to protect the leadership of Mayawati, drifting of its workers to the Aam Admi Party would have been stopped. It is not that they do not have the capacity to do so, if they could do to us. So the real enemies are within us. Is not it the height of casteism amongst so called Ambedkarites and supporters of BSP? Now Mayawati leadership cannot empower us as she is being at the verge of great fall. Even BSP grows, though there is no chance, yet it cannot secure dignity and rights for Dalits. At one point of time BSP has got the strength in Parliament of about forty MPs including Rajya Sabha, Mayawati did not allow to utilize the platform to raise the question about these people. She is so insulated that no one can meet and discuss. Dalits and Adivasis in the country should now rethink and get united under the leadership of Confederation. +++

Religious intolerance in india would have shocked Gandhi : Obama

6 February 2015. US President Barack Obama on Thursday said "acts of intolerance" experienced by religious faiths of all types in India in the past few years would have shocked Mahatma Gandhi. The comments came a day after the White House refuted suggestions that the US President's public speech in New Delhi, in which he touched on religious tolerance, was a "parting shot" aimed at the ruling BJP. Hours before winding up his three-day visit to India on January 27, Obama had said, "Every person has the right to practice his faith without any persecution, fear or discrimination. India will succeed so long as it is not splintered on religious lines. Your Article 25 says all people are equally entitled to the freedom of conscience and have the right to freely profess, practice and propagate religion. In both our countries, in all countries, upholding freedom of religion is the utmost responsibility of the government, but also the responsibility of every person."

Religious intolerance in india

On Thursday, at the high-profile National Prayer Breakfast, Obama said, "Michelle and I returned from India — an incredible, beautiful country, full of magnificent diversity — but a place where, in past years, religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other people of faith, simply due to their heritage and their beliefs — acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate that nation." However, he did not name any particular religion and said the violence is not unique to one group or one religion.

"Humanity has been grappling with these questions throughout human history. And lest we get on our high horse and think this is unique to some other place, remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ. In our home (Cont...on page 6)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya